



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 14 दिसम्बर, 2005/23 अग्रहायण, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 नवम्बर, 2005

संख्या टी0पी0टी0एफ0(6)2/2000. -प्रारूप संशोधन नियम नामतः हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (प्रथम संशोधन) नियम, 2005, हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का 4) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में समसंख्यक अधिसूचना तारीख 14-9-2005 द्वारा इनसे सम्भाव्य प्रभावित व्यक्तियों से हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का 4) की धारा 21 के अधीन यथा घोषित, इनके प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 23-9-2005 को प्रकाशित किए गए थे।

2. विधित अवधि के भीतर प्रारूप नियमों से सम्बन्धित जनमाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सरकार द्वारा विचार किया जा चुका है।

3. अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का 4) की धारा 21 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम. —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (प्रथम संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में अन्तिम जाकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निम्न 4-क का संशोधन. — हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1974 के विद्यमान नियम 4-क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

“4-क. कर के संवाय में विलम्ब के सिद्धान्त. — यदि मोटरयान का स्वामी अधिनियम की धारा 3 के अधीन देय कर का संदाय, उक्त नियमों के नियम 4 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या अधिनियम की धारा 3-क के अधीन धारा 3-क की उप-धारा (2) के उद्देश्यों के अनुसार अधिसूचित विनिर्दिष्ट तारीख तक, करने में अनफल रहता है तो कराधायक अधिकारी सुनवाई का व्यक्ति-युक्त अवसर देने के पश्चात, स्वामी को शास्ति का, उससे देय कर के 25 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से, संदत्त करने के निर्देश देगा :

परन्तु यह कि इस प्रकार उद्गृहीत शास्ति दिन-प्रतिदिन के आधार पर आनुपातिक रूप में परिकलित/संगणित की जाएगी यदि विलम्ब अवधि एक वर्ष से कम है और यह ऐसे स्वामियों से शास्ति की संगणना के समय पर देय कर की राशि से अधिक नहीं होगी।

परन्तु यह और भी कि शास्ति प्रत्येक माम की 16 तारीख को संगणित की जाएगी जो कि शास्ति के परिकलन के प्रयोजन के लिए परिनिश्चित समय बिन्दु होगी और शास्ति की ऊपरी सीमा, शास्ति की संगणना की तारीख को देय कर का संचयी बकाया होगी।”

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-  
प्रधान सचिव।

[Authoritative English text of Transport Department Notification No. TPT-F(6)-2/2000, dated 23-11-2005 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

## TRANSPORT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd November, 2005

No. TPT-F(6)2/2000. —Whereas the draft amendment rules titled as the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation (First Amendment) Rules, 2005 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-Ordinary) on 23-9-2005, vide notification of even number dated 14-9-2005 in pursuance of the provisions of Section 21 of Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972, for inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby as required under section 21 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act 1972, within a period of 30 days from the date of publication;

2. And, whereas the Government has considered the objections/suggestions received from general public on the said draft rules.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely :—

1. Short title.—(1) These rules shall be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation (First Amendment) Rules, 2005.

(2) These shall come into force from the date of final publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment to Rule-4A.*—For the existing rule 4-A of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation rules, 1974, the following shall be substituted, namely :—

*“4-A. Penalty for delay in payment of tax.*—If the owner of the motor vehicle fails to pay the tax due under section 3 of the Act, within the time specified in rule 4 of these rules or under section 3-A of the Act by the specified date notified as per provisions of sub-section (2) of section 3-A of the Act, the taxation authority after giving opportunity of being heard, shall direct the owner to pay the penalty at the rate of 25 percent per annum of the tax due from him:

Provided that penalty so levied shall be calculated/computed proportionately on day-to-day basis in case the delay period is less than one year and it shall not exceed the sum of tax due from such owner at the time of computing the penalty :

Provided further that the penalty shall be computed on the 16th day of every month which shall be the defined point of time for the purpose of calculating the penalty and the upper ceiling of penalty shall be the cumulative arrears of tax due on the date of computation of penalty”.

By order,

Sd/-  
Principal Secretary.

